सेना के शौर्य व वीरता पर सवाल उठानेवाले राष्ट्र विरोधी शक्तियों को बैलेट से जवाब देने की जरूरत है. क्योंकि राष्ट्र विरोधी सोच रखनेवाले कांग्रेस, झामुमो, राजद जैसे दल सेना की वीरता पर सवाल उठाते हुए सबूत मांग रहे थे. **रघुवर दास,** मुख्यमंत्री

2019 का चुनाव देश की दिशा व दशा तय करेगा. क्योंकि आज संवैधानिक संस्था संकट में है. संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है. आरक्षण को समाप्त करने की साजिश चल रही है. लोकतंत्र खतरे में है. **तेजस्वी यादव,** राजद.

गप्पू चचा

झोला टांगने वाले नेता जी लगे किनारे, मैडम को मिला टिकट

रांची. गप्पू चचा को अब चैन मिला. रांची, चतरा, कोडरमा की घोषणा आखिर भाजपा ने कर ही दी. कांग्रेस भी चतरा और रांची में पहले ही घोषणा कर चुकी है. कोडरमा से बाबूलाल लड़ेंगे. यानी सीन अब साफ हो गया है. गप्पू चचा रात-रात तक जगे रहते थे कि पता नहीं कब घोषणा कर दे. अब दिन में घोषणा हो गयी. अब गप्पू चचा गिरिनाथ को लेके परेशान हैं. उ बेचारा न ऐने का रहा, न उने का. राजद से भी बाहर हुए कि इधर से टिकट मिल जायेगा पर सुनील सिंह फिर बाजी मार लिये. कहां तो उनका टिकट कटना था, पर ऐसा सेटिंग किया कि टिकट बच गया. मैडम तो टिकट की गारंटी पर ही आयी थी, सो मिल गया. बेचारे झोला टांगने वाले नेता जी को किनारे लगवा दिया. गप्पू चचा कहते हैं कि रांची में संजइया तो गजबे हाइ जंप मारा. महानगर अध्यक्ष था, खादी बोर्ड लिया और अब ऐके बार हाइ जंप मारके सीधे लोकसभा का टिकट हथिया लिया. बेचारे चचा जान हाथ मलते रहे गये. उनकी घुरकी भी कोई काम नहीं आयी. गप्पू चचा कह रहे हैं कि चुनाव तो अबरी गजबे होगा. खूब मजा आयेगा.

ई ठीक है

कांग्रेस 55 साल से गरीबी हटाओ का नारा दे रही है, लेकिन गरीब और गरीब होते चले गये. कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम परिवारवाद की देन हैं. आप सभी से अपील है महागठबंधन के कीचड़ में कमल खिलाएं. फिर एक बार मोदी सरकार बनायें.

रघुवर दास, मुख्यमंत्री

इंदिरा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1971-73 के दौरान देश के कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ. इससे सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि कोयला खदानों में काम कर रहे लाखों मजदूरों के जीवन में सुधार आया. उन्हें वाजिब मजदूरी मिली और बीसीसीएल व सीसीएल जैसे उपक्रम अस्तित्व में आये. आज इनमें लाखों को रोजगार मिला है.

सुबोधकांत सहाय, कांग्रेस रांची लोकसभा

बूथ स्तर पर काम कर रहे अपने साथियों से मिल कर, उनका उत्साह और जोश देख मन प्रफुल्लित हो उठा. लोकसभा चुनाव 2019 में झारखंड एक नये दौर का नया और निडर सरकार चुनने जा रहा है. ऐसी सरकार जो झारखंड और झारखंडियों के हित को सर्वोपरि रखे. इस निर्माण में आप भी झामुमो के साथ जुड़ें.

हेमंत सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष झामुमो

यही है मेरी पसंद

जनता की समस्याओं को हल करने वाला हो हमारा सांसद

हमारा सांसद संवेदनशील, जनता के साथ आत्मीय संबंध रखनेवाला एवं क्षेत्र की जनता के सुख-दु:ख में सदैव साथ देनेवाला हो. जनता की समस्याओं के हल के लिए उचित प्लेटफार्म पर दृढ़ता से उनकी आवाज बने. समस्याओं के समाधान के लिए लगन, कर्मठता व प्रभावी रूप में एक सक्रिय प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करे. वह परिणाम देने व निष्पक्ष रह कर लोगों के बीच समानता की भावना से काम करता हो. अनेकों सांसदों की सांसद निधि बची रह जाती है और जनता समस्याओं से त्रस्त रहती है, ऐसा न सिर्फ चिंताजनक है, बल्कि लोक कल्याण के लिए की गयी व्यवस्था का तिरस्कार भी है. धन-बल, छल-प्रपंच, मनमर्जी का गलत व अमर्यादित रूप में प्रयोग सामाजिक, नैतिक, अध्यात्मिक व लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए घातक है. वैसी प्रवृत्ति का प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए. हमें वैसे सांसद चाहिए, जो समाज के लिए आदर्श हो.

डॉ श्रीमोहन सिंह, राज्य सचिव, भारत स्काउट-गाइड झारखंड राज्य शाखा.

इनकी भी सुनें

जनता के बीच रहता हो तथा क्षेत्र की समस्या को अपना समझता हो. क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेता हो. सिर्फ वोट के लिए जनता के बीच नहीं आये, जीतने के बाद भी वह क्षेत्र से जुड़ा रहे.

रमेश गुप्ता, सुभाष चौक निवासी

लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या मान कर उसका समाधान निकालने का प्रयास करे. चुने जाने के बाद वह अपनी जिम्मेवारियों को समझे तथा लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करे. क्षेत्र के लोगों से अपना संपर्क हमेशा बनाये रखे.

ज्योति पोद्दार, चार्टर्ड एकाउंटेंट सह अधिवक्ता

हमारा सांसद हमारे बीच से हो. जीतने के बाद भी उसका क्षेत्र से जुड़ाव रहे, तभी क्षेत्र की समस्याएं दूर होंगी. देशहित में काम करे. बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हरसंभव कदम उठाने के लिए सरकार को मजबूर कर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना लागू कराये.

कालीनाथ झा, सेवानिवृत शिक्षक

वैसा सांसद चुना जाना चाहिए, जो सभी के लिए सुलभ हो. निर्वाचित होने के बाद उनसे मिलना सरल हो. विकास ही उसका विजन हो. जनहित में अपने सांसद कोटे का समुचित उपयोग करे.

अजय कुमार, प्रेस प्रवक्ता, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टिशनर्स ईस्टर्न जोन.

आमने-सामने : सिंहभूम संसदीय सीट

2014 के लोकसभा चुनाव में सिंहभूम संसदीय सीट से भाजपा के लक्ष्मण गिलुवा ने जीत हासिल की थी. उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी गीता कोड़ा को 87,524 वोट से हराया था. तब श्री गिलुवा को 3,03,131 वोट मिले थे. गीता कोड़ा जय भारत सामंता पार्टी उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में थीं. सिंहभूम लोकसभा सीट के अंदर पश्चिम सिंहभूम के पांच और सरायकेला-खरसावां का एक विधानसभा क्षेत्र आता है. गिलुवा ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद में 513 सवाल उठाये. 31 बहस में हिस्सा लिया. 92 फीसदी उपस्थिति रही. सांसद गिलुवा ने अपने क्षेत्र की जनता का पूरा ख्याल रखने का दावा किया. वहीं प्रतिद्वंद्वी गीता कोड़ा ने क्षेत्र में विकास योजना भी लागू नहीं कराने का आरोप लगाया.

बिजली, पानी, फ्लाइओवर सब कुछ दिया : लक्ष्मण गिलुवा

शीन अनवर ▷ चक्रधरपुर

सांसद का दावा

सांसद लक्ष्मण गिलुवा ने कहा कि उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का पूरा ख्याल रखा है. पिछले पांच साल में क्षेत्र के लोगों को बिजली, पानी, फ्लाइओवर सब कुछ उपलब्ध कराया है. सभी छह विधानसभा क्षेत्रों में विकास के कार्य किये गये. चक्रधरपुर में पिछले 40 सालों से फ्लाइओवर नहीं बना था, लेकिन हमने पहल करके बनवाया. 70 सालों से अंधेरे में जी रहे गुदड़ी प्रखंड के 56 गांवों के लोगों तक बिजली पहुंचायी. चाईबासा फ्लाइओवर का निर्माण कार्य शुरू कराया. नोवामुंडी में फ्लाइओवर बनवाया. जिले का सबसे उपेक्षित प्रखंड गुदड़ी में दूरसंचार व्यवस्था बहाल करवायी. श्री गिलुवा ने कहा कि चक्रधरपुर में पानी की किल्लत दूर करायी. पनसुवां डैम से चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति योजना शुरू की गयी. नोवामुंडी के कुटिंगवा में पेयजल आपूर्ति योजना के तहत 62 गांवों में पानी की सप्लाइ प्रारंभ करायी. बंद पड़ी माइंस को लीज नवीकरण कर चालू कराया. इससे स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिला. सोनुवा से गुदड़ी तक पीडब्ल्यूडी की 45 किमी लंबी सड़क, चक्रधरपुर-टोकलो-कुचाई पथ, बांझीकुसुम-टोकलो-झरझरा पथ, चक्रधरपुर-सोनुवा-गोईलकेरा 45 किमी सड़क, सरायकेला से ओड़िशा सीमा तक 22 किमी पथ, चाईबासा मुख्य सड़क से कांड्रा तक 20 किमी पथ, हाता-चाईबासा 37 किमी एनएन-22 पथ का नर्मिण कराया गया. उन्होंने कहा कि चाईबासा में नया समाहरणालय भवन, कोल्हान विश्वविद्यालय का भवन, चक्रधरपुर, गोईलकेरा, आनंदपुर, सोनुवा, गुदड़ी में नये प्रखंड कार्यालय भवन का निर्माण करवाया. मनोहरपुर में वेदांता स्टील प्लांट लगाने की पहल की गयी है. इसके साथ ही गुदड़ी में विद्युत ग्रिड, मनोहरपुर के छोटानागरा में पेयजल आपूर्ति योजना प्रारंभ करायी गयी. आनंदपुर, कराईकेला, टोकलो व कुनाबेड़ा को अलग प्रखंड का दर्जा दिलाने में कोशिश की. कई पुल-पुलिया बनवाया. आदित्यपुर में 400 करोड़ की जलापूर्ति योजना व 200 बेड का अस्पताल, मझगांव में कन्यमनी नदी पर बड़ा पुल और मझगांव रेफरल अस्पताल में भवन बनवाया.

केंद्र की एक भी योजना नहीं, जिसे गिलुवा गिनायें : गीता कोड़ा

प्रतिनिधि ▷ चक्रधरपुर

विपक्ष का आरोप

इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट से चुनाव मैदान में उतरी गीता कोड़ा ने पिछले पांच वर्षों में सांसद लक्ष्मण गिलुवा द्वारा किये गये कार्यों को नकारती है. उन्होंने कहा कि वर्तमान सांसद के पास एक भी ऐसी केंद्र सरकार की योजना नहीं है, जिसे वह जनता को बता सके. केंद्र सरकार से योजनाएं लाकर क्षेत्र का विकास करना चाहिए था. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. जब काम ही नहीं किये, तो जनता के पास जायेंगे कैसे. इसलिए राज्य सरकार की योजनाओं को गिनवा रहे हैं. जिन पर विधायकों को श्रेय मिलना चाहिए था, उसका श्रेय सांसद हासिल करना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि मेरी निगाह में लक्ष्मण गिलुवा की पूरे पांच सालों में एक भी उपलब्धि नहीं है. गीता कोड़ा ने कहा कि चक्रधरपुर में जिस ओवरब्रिज का निर्माण कराने की बात कह रहे हैं, असल में उसकी प्रक्रिया राज्य की यूपीए सरकार ने शुरू की थी. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में 2007-08 में इसे मंजूरी दी गयी थी. आज भी उस ओवरब्रिज में अंधेरा है, बिजली को कोई व्यवस्था नहीं है, अंडर पास-वे के लिए स्थानीय जनता लड़ाई लड़ रही है. यदि सांसद जी को जनता के हितों की फिक्र होती, तो निश्चित रूप से इन दोनों समस्याओं का हल निकालते. लेकिन उन्होंने इसकी पहल तक नहीं की. गीता कोड़ा ने कहा कि विधायकों के प्रयास से जितने भी काम हुए, सबका श्रेय सांसद लेना चाह रहे हैं. एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूं - जनता अगर गौर करेगी, तो पायेगी कि प्रखंड कार्यालय भवनों या माल गोदामों या पुल- पुलियों का निर्माण केंद्र सरकार नहीं करती, सांसद का इसके निर्माण में कोई रोल ही नहीं होता. इसे राज्य सरकार विधायकों की अनुशंसा पर ही करती है, लेकिन सांसद अपने कार्यों की सूची में इन्हें भी शामिल कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर सांसद जी काम करते तो आदर्श गांवों में यह दिखता. कई गांवों को आदर्श गांव बनाने के लिए सांसद ने गोद लिया था. इनमें एक गांव गोइलकेरा का डलाईकेला है, लेकिन विकास आज भी शून्य है. गांव वाले ठगा महसूस कर रहे हैं. गांव में पानी, स्वास्थ्य, मकान और प्राथमिक शिक्षा तक मुहैया नहीं है.

वर्ष 2014 का चुनावी आंकड़ा

विजेता	पार्टी	वोट मिले थे	उप विजेता	पार्टी	वोट मिले	कितने वोट से हारे
लक्ष्मण गिलुवा	भाजपा	303131	गीता कोड़ा	जय भारत सामंता पार्टी	215607	87524

तीन लोकसभा चुनावों का आंकड़ा

वर्ष	जो जीते	पार्टी	कितना वोट मिला	जो हारे	पार्टी	कितना वोट मिला	कितने वोट से हारे
2004	बागुन सुंब्रई	कांग्रेस	221343	लक्ष्मण गिलुवा	भाजपा	162147	59196
2009	मधु कोड़ा	निर्दलीय	256827	बड़कुंवर गगराई	भाजपा	167154	89673

झारखंड में करीब एक लाख से अधिक कोयलाकर्मी

लोकसभा की कई सीटों पर निर्णायक होंगे कोयलाकर्मी

मनोज सिंह ▷ रांची

गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, दुमका, रांची, पलामू, चतरा है प्रभाव क्षेत्र

कहां, कितने कर्मी

कंपनी	संख्या
बीसीसीएल	48513
सीसीएल	40681
सीएमपीडीआइ	3384
इसीएल	5000 (करीब)

झारखंड का बड़े इलाके में कोयला खनन का काम होता है. कोयला मजदूरों की समस्या हमेशा राजनीति को प्रभावित करती रही है. कुछ सीट कोयलाकर्मियों के मुद्दे पर तय होता है. कुछ सीटों पर इनका अप्रत्यक्ष तो कुछ पर प्रत्यक्ष असर है. इस कारण कई मजदूर यूनियनों से जुड़े नेता भी सक्रिय राजनीति में शामिल हैं. झारखंड में कोयला मजदूरों व अधिकारियों की भी बड़ी संख्या है. वोटर के रूप में यह चुनावी आंदोलन को प्रभावित करते हैं. झारखंड में करीब एक लाख से अधिक कोयलाकर्मी हैं. इनका असर गिरिडीह, धनबाद, गोड्डा, दुमका, रांची, पलामू, चतरा संसदीय क्षेत्र में पड़ सकता है. कई लोकसभा क्षेत्र में तो यह निर्णायक भूमिका में होंगे.

झारखंड में संचालित हैं चार कंपनियां : झारखंड में चार कोयला कंपनियां संचालित हैं. तीन कंपनियों का मुख्यालय झारखंड में है. एक कंपनी का मुख्यालय तो प बंगाल में है, लेकिन झारखंड के कुछ इलाकों में इनका खनन का काम है. सीसीएल और सीएमपीडीआइ का मुख्यालय रांची में है. इसी तरह बीसीसीएल का मुख्यालय धनबाद में है, जबकि इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय प बंगाल में है. इन कर्मियों के मुद्दे राज्य स्तर के नहीं है. राष्ट्रीय स्तर पर लिये जाने वाले निर्णय से कंपनियों के कामकाज प्रभावित होते हैं.

वोट तो ले लेते हैं, लेकिन मुद्दा नहीं उठाते हैं : कोयला क्षेत्र में काम करनेवाले श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों का मानना है कि हमलोगों के वोट से तो प्रतिनिधि चुन लिये जाते हैं, लेकिन हमारी आवाज नहीं उठाते हैं. ऐसा भारतीय मजदूर संघ, सीटू, एटक, एचएमएस के प्रतिनिधियों का भी कहना है. सीटू के आरपी सिंह कहते हैं कि झारखंड के एक भी लोकसभा सदस्य ने मजदूरों की समस्या नहीं उठायी. एक बार तपन सेन और एक टीडीपी की सांसद ने आवाज उठाया था. एटक नेता लखन लाल महतो कहते हैं कि कोयला क्षेत्र की कई समस्या है. हाल के दिनों में कई ऐसे मामले थे, जो सीधे कोयलाकर्मियों को प्रभावित करते रहे. इसमें व्यावसायिक खनन, आउट सोर्सिंग, अनुकंपा व मेडिकल अनफिट नौकरी आदि मुद्दों पर भी कोई आवाज नहीं उठाते हैं. चुनाव जीतने के बाद निजी व्यवस्था में लग जाते हैं. भारतीय मजदूर संघ के बिंदेश्वरी प्रसाद का कहना है कोयला क्षेत्र का ट्रेड यूनियन खुद काफी मजबूत होता है. कभी-कभी जरूरत पड़ने पर सांसदों के पास गये हैं, सहयोग नहीं किया. कई नेता कोयला कंपनी चला रहे हैं, लेकिन हाइपावर कमेटी की अनुशंसा खुद लागू नहीं करते हैं.

संगठन से तालमेल अन्नपूर्णा की चुनौती

- टिकट को लेकर चली जद्दोजहद व दलबदल से अपनों के भितरघात की आशंका

विकास ▷ कोडरमा

प्रदेश राजद अध्यक्ष पद का त्याग कर भाजपा का दामन थामनेवाली पूर्व मंत्री अन्नपूर्णा देवी को कोडरमा लोकसभा से टिकट मिल गया. लंबे समय से टिकट को लेकर चल रही जिच के बाद भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने अन्नपूर्णा के नाम का एलान किया तो लोग अब जीत-हार को लेकर समीकरण बैठाने लगे हैं. राजनीतिक जानकारों के अनुसार भाजपा से टिकट प्राप्त कर अन्नपूर्णा ने पहला जंग जरूर जीत लिया है, पर जिस तरह टिकट को लेकर वर्तमान सांसद डॉ रवींद्र राय व अन्य दावेदार अंतिम समय तक डटे रहे, उससे भितरघात की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है. रवींद्र राय ने तो एक-दो दफे बकायदा सोशल मीडिया पर टिकट को लेकर अपनी राय जगजाहिर की. यही नहीं भाजपा जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह समेत कई मंच मोर्चा के नेताओं ने राष्ट्रीय नेतृत्व को पत्र लिख कर डॉ रवींद्र राय को ही टिकट दिये जाने पर जीत की गारंटी बतायी थी. अब जब डॉ राय की जगह अन्नपूर्णा को टिकट थमाया गया है, तो पार्टी संगठन के अंदर अलग तरह की चर्चा शुरू हो गयी है. अन्नपूर्णा के लिए सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के स्थानीय संगठन के साथ तालमेल बैठाने की होगी. जो भाजपाई वर्षों तक राजद के शासन को कुशासन बताते हुए अन्नपूर्णा देवी का विरोध करते रहे, उन्हें अब अन्नपूर्णा के लिए भाजपा से प्रचार करना होगा. इस स्थिति में संगठन के अंदर नाराजगी व बिखराव भी देखने को मिल सकता है.

खराब रिपोर्ट कार्ड व सरकार से अलग राह ने कटवा दिया टिकट! पांच साल तक कोडरमा के सांसद रहे डॉ रवींद्र राय का टिकट कटने को लेकर कई कारण बताये जा रहे हैं. सबसे बड़ा कारण अंतिम समय में बदली स्थितियां हैं. इसके अलावा खराब रिपोर्ट कार्ड व राज्य सरकार से कई मुद्दों पर अलग राय रखने को भी ठोस कारण माना जा रहा है.

पति रमेश यादव भी लड़े थे : एक ही लोकसभा सीट से पति-पत्नी दोनों के द्वारा सांसद का चुनाव लड़ने का संयोग कोडरमा में भी बनने जा रहा है. अन्नपूर्णा देवी जहां इस बार भाजपा की प्रत्याशी होंगी, वहीं उनके पति स्वर्गीय रमेश प्रसाद यादव 1996 में इसी सीट से जनता दल के प्रत्याशी थे. हालांकि, उस समय उन्हें भाजपा के रीतलाल प्रसाद वर्मा से हार का सामना करना पड़ा था. रीतलाल वर्मा को जहां 243295 वोट मिले थे, वहीं रमेश यादव को 196341 वोट मिले थे. रमेश को तत्कालीन सांसद मुमताज अंसारी की जगह उम्मीदवार बनाया था. इसमें रमेश यादव को हार का सामना करना पड़ा.

ईमानदारी के लिए आज भी याद किये जाते हैं तीन बार विधायक व मंत्री और दो बार सांसद रहे ललित उरांव

गांव के साधारण मकान में रहता है बाबा का परिवार

- ललित उरांव पांच बार लोकसभा चुनाव लड़े थे. तीन बार हारे, दो बार 1991 व 1996 में चुनाव जीते थे, तीन बार 1969, 1977 व 1980 में चुनाव जीत कर विधायक बने थे.

दुर्जय पासवान/सुरेश ▷ गुमला

परिवार के सदस्यों के साथ ललित उरांव. फाइल फोटो.

अपने घर के समीप खड़ास्वर्गीय ललित उरांव का पुत्र मंगलाचरण .

लोहरदगा संसदीय सीट से 1991 व 1996 में दो बार भाजपा की टिकट से संसदीय चुनाव जीतने वाले बाबा के परिवार के पास आज भी कुछ कमरों का एक मंजिला घर है. बाबा के नाम से प्रसिद्ध रहे ललित उरांव तीन बार बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे. संयुक्त बिहार में मंत्री भी रहे. अपने आदर्शों पर अटल रहने वाले श्री उरांव का परिवार आज भी खेती-बारी कर जीवन यापन कर रहा है. परिवार के कुछ सदस्य राजनीतिक दलों के सदस्य जरूर हैं, लेकिन अभी तक चुनावी राजनीति से दूर. श्री उरांव तीन बार सिसई विधानसभा से 1969, 1977 व 1980 में चुनाव जीत कर विधायक बने थे. 1969 में बिहार सरकार में आदिवासी कल्याण मंत्री व 1977 में वन मंत्री बने. 1974 के जयप्रकाश आंदोलन में हिस्सा लिया था. उस समय उन्हें तिहाड़ जेल जाना पड़ा था. ललित उरांव का 27 अक्तूबर 2003 को टाटा में निधन हो गया था. आज भी उनकी ईमानदारी व काम करने के तरीके को लोग याद करते हैं. सांसद व विधायक रहते हुए भी वे खेती-बारी से जुड़े रहे. लोगों के दिलों में राज करते थे. उनके नाम से ही गुमला शहर में ललित उरांव बस पड़ाव बना है. इनके राजनीति जीवन में लगनशील, शालीनता, ईमानदारी, सादगी व उच्च विचार था. स्वर्गीय ललित उरांव के एक पुत्र व तीन पुत्री हैं. 1981 में ललित उरांव द्वारा पोटरो गांव में बनाये गये घर में ही उसका बेटा मंगलाचरण उरांव अपने परिवार के साथ रहता है. वर्तमान में स्वर्गीय ललित उरांव के पुत्र मंगलाचरण उरांव भाजपा के कार्यकर्ता हैं.मंगलाचरण बताते हैं कि उनके पिता स्व ललित उरांव ने मीडिल स्कूल तक की पढ़ाई सिसई मध्य विद्यालय से की थी, हाइस्कूल गुमला से मैट्रिक की परीक्षा पास की. रांची से इंटर पास के बाद पढ़ाई छोड़ खेती-बारी में लग गये. सामाजिक कार्य में रुचि लेने लगे. इसी बीच शिक्षक बने और रामवि बिशुनपुर में हेड मास्टर बने. ललित उरांव 1962 में कांग्रेस के कार्तिक उरांव के साथ राजनीति में आये. 1962 में ही कांग्रेस पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़े, पर जीत नहीं मिली. इसके बाद 1965 में जनसंघ पार्टी में शामिल हो गये. 1969 में जनसंघ से पहली बार विधायक बने और बिहार में आदिवासी कल्याण मंत्री बनाये गये थे.

राष्ट्रीय दलों के नेताओं ने पिछले पांच साल के कार्यकाल में कभी भी आदिवासी जिले का दौरा नहीं किया. अब वोट पाने के लिए दौरे कर रहे हैं. **नवीन पटनायक**, सीएम ओड़िशा

ईसी (चुनाव आयोग) के आरोपों के बाद राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए. **पी चिदंबरम**, कांग्रेस

असम : पहला चरण

34 प्रतिशत उम्मीदवार मैट्रिक पास या उससे कम

डिब्रूगढ़. असम में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 41 उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता मैट्रिक पास या उससे कम है. इनमें भाजपा के मौजूदा सांसद भी शामिल हैं. चुनाव हलफनामों में यह बात सामने आयी है. हालांकि इस सूची में आइआइटी के एक पूर्व छात्र, राजनीति विज्ञान के एक सेवानिवृत्त प्राध्यापक, कानून और स्नातकोत्तर डिग्रीधारक भी शामिल हैं. असम की 14 में से पांच लोकसभा सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होना है. डिब्रूगढ़ से भाजपा के मौजूदा सांसद और इस बार भी चुनाव लड़ रहे रामेश्वर तेली हाइस्कूल पास हैं.

कांग्रेस-भाजपा के पांच को छोड़ सभी उम्मीदवार करोड़पति

गुजरात लोस चुनाव

- मेहसाणा से कांग्रेस उम्मीदवार अंबालाल पटेल दलों के सबसे अमीर प्रत्याशी, कुल घोषित पूंजी 69.9 करोड़ रुपये
- सबसे अमीर महिला प्रत्याशी जामनगर की भाजपा सांसद पूनम मादम, कुल संपत्ति 42.7 करोड़ रुपये

एजेंसियां ▸ अहमदाबाद.

गुजरात में 26 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी मैदान में उतरे भाजपा और कांग्रेस के पांच उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवार करोड़पति हैं. उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों के साथ जमा किये गये शपथ पत्रों से यह पता चला है. एक करोड़ रुपये से कम आय वाले पांच में से चार उम्मीदवार जनजातीय समुदाय से संबंध रखते हैं.

दोनों दलों के सबसे अमीर उम्मीदवारों में कांग्रेस के मेहसाणा से उम्मीदवार अंबालाल पटेल शामिल हैं,

सबसे कम अमीर उम्मीदवार कांग्रेस के जीतू चौधरी, कुल पूंजी 66.1 लाख रुपये

जिनकी घोषित पूंजी 69.9 करोड़ रुपये है. भाजपा उम्मीदवार और नवसारी से मौजूदा सांसद चंद्रकांत पटेल की घोषित पूंजी 44.6 करोड़ रुपये हैं. जामनगर से भाजपा सांसद पूनम मादम की घोषित पूंजी 42.7 करोड़ रुपये है वह इस बार भी जामनगर से चुनाव लड़ रही हैं. मेहसाणा से भाजपा की उम्मीदवार शारदाबेन पटेल के पास 44 करोड़ रुपए की पूंजी है. रमेश धाडुक ने 35.75 करोड़ रुपए की पूंजी की घोषणा की है. कांग्रेस के तीन और भाजपा के दो उम्मीदवारों की घोषित पूंजी एक करोड़ रुपए से कम है. भरूच से भाजपा सांसद मनसुख वसावा की घोषित पूंजी 68.35 लाख रुपये, कांग्रेस उम्मीदवार शेरखान पठान की घोषित पूंजी 33.4 लाख रुपये, कच्छ से कांग्रेस उम्मीदवार नरेश माहेश्वरी की कुल पूंजी 38.13 लाख रुपये, भाजपा उम्मीदवार गीताबेन राठवा की घोषित पूंजी 86.3 लाख रुपए अैर कांग्रेस उम्मीदवार जीतू चौधरी की कुल घोषित पूंजी 66.1 लाख रुपये है.

कुल पूंजी में उम्मीदवारों, उनके जीवन साथियों एवं आश्रितों की चल एवं अचल संपत्ति शामिल होती है. गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के लिए 573 उम्मीदवार मैदान में हैं और यहां 23 अप्रैल को चुनाव होंगे.

चुनाव अपडेट

1 भाजपा ने उप्र से चार और प्रत्याशियों की सूची जारी की

लखनऊ. भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से चार और प्रत्याशियों की सूची शनिवार को जारी की. आजमगढ़ में लालगंज सुरक्षित सीट से सांसद नीलम सोनकर प्रत्याशी होंगी, जबकि झांसी से सांसद तथा केंद्रीय मंत्री उमा भारती की जगह अनुराग शर्मा और बांदा में सांसद भैरो प्रसाद मिश्रा की जगह आरके पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है. फूलपुर से प्रयागराज की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केशरी देवी पटेल को प्रत्याशी घोषित किया गया है. पार्टी ने लखीमपुर खीरी के निघासन विधानसभा के उप चुनाव के लिए शशांक वर्मा को प्रत्याशी बनाया है.

2 अमित शाह ने गांधीनगर में किया रोडशो

अहमदाबाद. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के 39वें स्थापना दिवस पर शनिवार को गांधीनगर में रोडशो किया. शाह गांधीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं. अहमदाबाद

के सरखेज इलाके से शुरू हुए रोडशो से पहले शाह ने जनसंघ के संस्थापक दीन दयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीरों पर माल्यार्पण किया. शाह ने 'जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है, सारा का सारा हमारा है' के नारे भी लगाये. पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में शाह की आलोचना की थी कि वह कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का दिवास्वप्न देख रहे हैं.

3 अरुणाचल प्रदेश : लोकसभा चुनाव का पहला वोट पड़ा

ईटानगर. देश के पूर्वी छोर अरुणाचल प्रदेश में आइटीबीपी के जवानों ने शनिवार को लोकसभा चुनाव, 2019 का पहला वोट डाला. यहां लोकसभा चुनाव पहले चरण में 11 अप्रैल को होना है. गौरतलब है कि लोकसभा चुनावों के तय कार्यक्रम से पहले सर्विस वोटर्स द्वारा मतदान किया जाता है. इसके तहत अरुणाचल प्रदेश में तैनात इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (आइटीबीपी) की अरुणाचल प्रदेश के लोहितपुर स्थित यूनिट ने मतदान किया. जवानों ने गुप्त डाक मतपत्र के जरिये अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

4 थल सेना के पूर्व उप प्रमुख शरत चंद भाजपा में हुए शामिल

नयी दिल्ली. थल सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) शरत चंद शनिवार को पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की मौजूदगी में भाजपा में

शामिल हो गये. शरत चंद जून 1979 में गढ़वाल राइफल्स में शामिल हुए थे और वह पिछले साल एक जून को थल सेना के उप प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हुए. वह थल सेना में कई अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. उन्होंने कहा, आज के वैश्विक परिदृश्य में देश को मजबूत नेतृत्व की जरूरत है. मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से प्रेरित हूं. इसी कारण में भाजपा में शामिल हो रहा हूं.

5 राहुल को सुषमा की सीख भाषा की गरिमा रखें

नयी दिल्ली. वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को लेकर राहुल गांधी के बयान पर वरिष्ठ भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने एतराज जताया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष भाषणों में भाषा की गरिमा बनाये रखें. राहुल ने शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी पर आडवाणी को अपमानित करने का आरोप लगाया था और कहा था कि जूता मार के उन्हें (आडवाणी को) स्टेज से उतार दिया. सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया कि आडवाणी जी हमारे पिता तुल्य हैं. आपके शब्दों ने हमें बहुत आहत किया है. कृपया अपने भाषण में गरिमा बनाये रखें. वहीं, पीयूष गोयल ने कहा कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं.

कार्टून कोना — बीबीसी

जोर आजमाइश. हर बार मतदाता बदलते रहे हैं अपना सांसद, सब को दिया मौका

तीर्थनगरी हरिद्वार में भाजपा को रोकने के लिए राजनीतिक ध्रुवीकरण की लड़ाई

नेशनल कंटेंट सेल

तीर्थनगरी हरिद्वार में हिंदुत्व, गंगा, एयर स्ट्राइक के साथ ही स्थानीय मुद्दों की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है. हिंदुत्व के एजेंडे के लिहाज से मुफीद इस सीट को हर हाल में बरकरार रखने का दबाव भाजपा पर है. कांग्रेस और बसपा पर भी दबाव कम नहीं है. दिलचस्प स्थिति अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के वोटों को लेकर बन रही है. कांग्रेस और बसपा जहां इनके ध्रुवीकरण के लिए ताकत झोंक रही हैं, वहीं भाजपा इनके बिखराव से अपनी जीत का रास्ता तय होता देख रही है. पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद डॉ रमेश पोखरियाल निशंक यहां से फिर भाजपा प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस ने पूर्व विधायक अंबरीष कुमार को उतारा है. कांग्रेस अपने सबसे मजबूत नेता पूर्व सीएम हरीश रावत को उतारने की तैयारी में थी, लेकिन बात नहीं बनी. बसपा ने अंतरिक्ष सैनी पर दांव खेला है.

इस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 14 विधानसभा सीटें हैं और सब में अलग-अलग मुद्दों का असर दिखता है. समान रूप से हिंदुत्व-गंगा, एयर स्ट्राइक जैसी बातें हैं, लेकिन कहीं पर गन्ना किसानों का बकाया, तो कहीं पर रुड़की से देवबंद तक बिछाये जा रहे रेलवे ट्रेक के एवज में अधिग्रहित दस गांवों की जमीन और उसके मुआवजे का मामला प्रभावी है.

मोदी सरकार ही भारत का भला कर सकती है. जहां तक सांसद के रूप में काम का सवाल है, क्षेत्र में इस समय 25 हजार करोड़ रुपये के विकास कार्य चल रहे हैं.
डॉ रमेश पी निशंक, भाजपा प्रत्याशी

पिछले पांच वर्षों में समस्याओं का अंबार खड़ा हुआ है. गन्ना किसानों से लेकर तमाम समस्याएं हैं. 70% रोजगार की बात छलावा साबित हुई. भाजपा ने लोगों को छला है.
अंबरीष कुमार, कांग्रेस प्रत्याशी

भाजपा-कांग्रेस ने जनभावनाओं से खिलवाड़ किया है. बसपा को लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है. जीत तय है.
अंतरिक्ष सैनी, बसपा प्रत्याशी

हरीश को मिली थी ताकत, जीत के बाद खूब चमके

- कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सीएम हरीश रावत को 2009 में जब एक अदद चुनाव जीतने की सबसे बड़ी जरूरत थी, तब हरिद्वार लोकसभा सीट ने उनका साथ दिया था.
- इससे पहले, कुमाऊं की अल्मोड़ा सीट से ही हरीश रावत चुनाव लड़ते थे. अस्सी के दशक में उन्होंने वहां से मुरली मनोहर जोशी को तीन बार पराजित किया, लेकिन नब्बे के दशक में राम लहर के बाद भाजपा के बची सिंह रावत ने चार बार हरीश रावत को वहां परास्त किया.
- नया दांव खेलते हुए हरीश रावत 2009 में हरिद्वार सीट पर आये, तो उन्हें शानदार जीत मिली.

स्थानीय रोजगार का मुद्दा बरकरार

2000 में अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हरिद्वार जिले में करीब 1200 से ज्यादा फैक्ट्रियां लगी हैं. इनमें लाखों लोग रोजगार से जुड़े हैं. इसके बावजूद स्थानीय युवाओं को रोजगार का मुद्दा अभी भी जिंदा है. तत्कालीन एनडी तिवारी सरकार ने सिडकुल की स्थापना के समय 70% रोजगार स्थानीय युवाओं को देने का शासनादेश जारी किया था.

जमीन के मुआवजे का इंतजार

रुड़की से देवबंद तक बिछाये जा रहे रेलवे ट्रैक की एवज में हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के करीब दस गांव की जमीन अधिग्रहित की गयी है. एक बार बंद हो गयी इस परियोजना को मोदी सरकार ने दो साल पहले फिर से शुरू किया था. गांवों की हजारों बीघा जमीन अधिग्रहित की गयी है, लेकिन जमीन मुआवजे का मामला अब भी अटका है.

कब किसे कितने वोट मिले

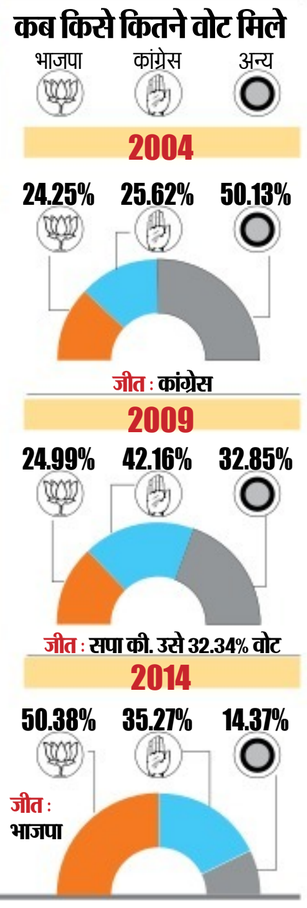

उत्तर प्रदेश

डिंपल ने दाखिल किया नामांकन पत्र

कन्नौज. सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और कन्नौज से मौजूदा सांसद डिंपल यादव ने शनिवार को यहां अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. डिंपल यादव दोपहर करीब डेढ़ बजे कलेक्ट्रेट पहुंचीं, जहां उन्होंने नामांकन पत्र के दो सेट दाखिल किये. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सपा

उपाध्यक्ष किरणमय नंदा व महासचिव रामगोपाल यादव, बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, जया बच्चन भी मौजूद थीं.

नामांकन से पूर्व डिंपल और अखिलेश ने रथ पर सवार होकर रोड शो किया. अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार देश में परिवर्तन की लहर है और केंद्र में गठबंधन की सरकार बनेगी, जिसमें सपा, बसपा, रालोद की महत्वपूर्ण भूमिका होगी. यादव ने कहा कि कन्नौज ने लोहिया और मुलायम सिंह यादव को जिता कर भेजा. हमें भी कन्नौज की जनता ने तीन बार आशीर्वाद दिया और दो बार डिंपल यादव को कन्नौज से सांसद बनने का मौका दिया. उन्होंने कहा कि भाजपा ने वादों के खिलाफ काम किया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है. युवा, किसान, मजदूर, व्यापारी, सभी परेशान हैं. भाजपा सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है.

महागठबंधन

तीनों नेताओं की साझा रैली आज

लखनऊ. बसपा, सपा और रालोद गठबंधन की लोकसभा चुनाव के लिए पहली संयुक्त रैली रविवार को सहारनपुर के देवबंद से होगी. यहां पहले चरण में 11 अप्रैल को चुनाव होने हैं. बसपा द्वारा शनिवार को जारी एक बयान में कहा गया कि देवबंद की यह रैली जामिया तिब्बिया मेडिकल कॉलेज के पास आयोजित की गयी है.

इस रैली को बसपा सुप्रीमो मायावती संबोधित करेंगी. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि देवबंद की रैली में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहेंगे. यह पहली बार होगा कि गठबंधन की तीनों पार्टियों के प्रमुख नेता एक मंच पर होंगे. रालोद प्रवक्ता अनिल दुबे ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष अजित सिंह और उपाध्यक्ष जयंत चौधरी कल देवबंद में रैली को संबोधित करेंगे. गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों पर हो रहे आम चुनाव में बसपा, पार्टी व आरएलडी पहली बार गठबंधन बना कर चुनाव लड़ रही हैं.

कांग्रेस का आयोग से सवाल

सत्तासीन ताकतों को आईना दिखाने से घबराहट क्यों

एजेंसियां ▸ नयी दिल्ली

कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार की हालिया टिप्पणियों पर चुनाव आयोग के कदम को लेकर कटाक्ष करते हुए शनिवार को आरोप लगाया कि चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब मोदी कोड ऑफ कंडक्ट बन गया है. पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा कि आदित्यनाथ भारतीय सेना का अपमान करते हैं और चुनाव आयोग उन्हें 'प्रेम पत्र' लिखता है. नीति आयोग के उपाध्यक्ष न्याय योजना को कोसते हैं और चुनाव आयोग कहता है, 'आगे से मत करें'. आखिरकार चुनाव आयोग

सत्तासीन ताकतों को सच्चाई का आईना दिखाने से घबरा क्यों रहा है?

वहीं, खबर है कि चुनाव आयोग ने उप्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके 'मोदीजी की सेना' वाले बयान पर नाराजगी जताते हुए भविष्य में अपनी टिप्पणियों में सावधानी बरतने को कहा है. आयोग ने राजीव कुमार द्वारा की गयी आलोचना को भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है.

कैमरे की नजर से

अपने निर्वाचन क्षेत्र में पूजन को कतार में

केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा प्रत्याशी स्मृति इरानी ने शनिवार को अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र अमेठी के काली मंदिर में पूजा अर्चना की. नवरात्र के अवसर पर देवी की पूजा करने पहुंची स्मृति ने अपनी बारी की प्रतीक्षा कतार में लग कर की.

ट्विटर/फेसबुक कोना

भाजपा व स्वयं पीएम मोदी अपनी संभावित हार से इतने भयभीत हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि वे किस पर क्या व कैसा मिथ्या आरोप लगा रहे हैं. आतंकियों को छोड़ने की गलत परंपरा भाजपा सरकारों की है, बसपा की नहीं.
मायावती, बसपा प्रमुख

'विकास' पूछ रहा है, गोरखपुर में सांसद जी को मठाधीशी का जो झोला भर प्रसाद मिला है, क्या उसे वे पूरा गटक जायेंगे या किसी से बांटेंगे भी? उन्हें जनता को यह हर हाल में बताना चाहिए.
अखिलेश यादव, सपा प्रमुख

पश्चिमी यूपी को सबसे ज्यादा जख्म सपा-बसपा की सरकारों ने दिये. बहुसंख्यकों से अन्याय और अल्पसंख्यकों को तवज्जो दी गयी. उनके समय में 39 चीनी मिलें बंद हुईं. पांच वर्षों से गन्ना मूल्य बकाया था. हमने दो वर्षों में ही 61 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया.
योगी आदित्यनाथ, सीएम यूपी

फ्लैश बैक — वक्त के मिजाज के साथ बदलते रहे हैं चुनावी नारे और जुमले

कभी इंदिरा को हटाने, तो कभी सत्ता में लाने को लगे नारे

डॉ आरके नीरद

नारे और जुमले चुनाव के ऐसे पहलू हैं, जिनमें राजनीतिक दलों की सोच और काल-परिस्थिति के अक्स पूरी शिद्दत से उतारे जाते हैं. इसे चूंकि हर बार चुनावी समीकरण और सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं. इसलिए चुनावी नारे और जुमले भी बदल जाते हैं. इन नारों में समय और समाज का मिजाज भी छिपा होता है. जिस देश में 1977 में 'इंदिरा हटाओ, देश बचाओ' के नारे ने केंद्र की सत्ता से कांग्रेस को उखाड़ फेंका, उसी देश में 1980 के चुनाव में 'आधी रोटी खायेंगे, इंदिरा को जितायेंगे' के नारे ने सत्ता में उसकी वापसी का रास्ता खोला. चुनावी नारों ने जनता को कुछ दिया हो या नहीं, दलों को अपने पक्ष में हवा बनाने में खूब मदद की है. 1971 में 'गरीबी हटाओ', इंदिरा गांधी के इस नारे ने देशभर के गरीबों को पहली बार राजनीतिक सोच की मुख्य धारा से जोड़ा. तब ऐसा करना राजनीतिक परिस्थितियों की दृष्टि से इंदिरा गांधी की विवशता थी, क्योंकि तब रोटी, कपड़ा और मकान जैसे सवालों के साथ दूसरे राजनीतिक दल तो चुनौती दे ही रहे थे, वर्चस्व के सवाल पर कांग्रेस की आंतरिक खींचतान की भी चुनौतियां इंदिरा गांधी को मिल रही थीं. राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे इंदिरा गांधी की लेफ्ट ओरिएंटेड पॉलिसी कहा. हालांकि जल्द ही इस नारे का आकर्षण खत्म हो गया और लोगों का इससे मोहभंग हुआ. परिणाम हुआ कि कांग्रेस पर 'गरीबी नहीं, गरीब हटाओ' की तोहमत भरी जुमलेबाजी हुई. यही हश्र 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के दिये नारे 'सब के खाते में 15 लाख' का हुआ. 2014 के आम चुनाव में इस नारे ने लोगों पर खूब असर डाला, मगर बाद में काले धन की वापसी और 15 लाख के सवाल पर जब केंद्र सरकार घिर गयी, तब भाजपा ने ही यह कह कर इसकी हवा निकाल दी कि यह चुनावी जुमला था. भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ने मोदी सरकार के 'सब का साथ, सब का विकास' के नारे पर संदेह पैदा कर दिया. अब तो इंदिरा गांधी के 'गरीबी हटाओ' की तर्ज पर इस नारे पर भी 'सब का साथ, खास का विकास' की तोहमत भरी जुमलेबाजी की जाने लगी है. एक नारा और भी बेमौत मरता दिख रहा है. वह है 'न खाऊंगा, न खाने दूंगा'. इन सबके बावजूद, चुनाव और नारों का रिश्ता कमजोर नहीं हुआ. दरअसल, चुनावी नारों का अपना समाजशास्त्रीय और यथार्थवादी पक्ष भी है. इनका सामाजिक मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव होता है. यह चुनाव अभियान और कार्यकर्ताओं में जोश पैदा करता है. इसलिए इसमें आक्रामकता का समावेश करने के भरपूर प्रयास होते रहे हैं. इस प्रयास में कई बार इस आक्रामकता ने राजनीतिक मर्यादा और सामाजिक सौहार्द पर सीधा प्रहार किया है. इसके प्रभात भी नकारात्मक हुए हैं, लेकिन चुनावी जुनून में इसकी परवाह तब तक नहीं की गयी, जब तक कि राजनीतिक दलों को इससे नुकसान नहीं पहुंचा.

रोचक संवाद होता रहा है नारों में

सन 60 के दशक में कांग्रेस के खिलाफ जनसंघ पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में उतरा था. उसका चुनाव चिह्न दीपक था. कांग्रेस का चुनाव चिह्न जोड़ा बैल था. तब जनसंघ ने नारा दिया था : **'जली झोंपड़ी-भागे बैल, यह देखो दीपक का खेल'**. कांग्रेस ने इसके जवाब में नारा लगाया : **'इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं'**. ये दोनों नारे बाद के सालों में भी लोगों के जेहन में गूंजते रहे.